

अध्याय V: निष्कर्ष

भारतीय वायु सेना 1966 से 1987 दौरान निर्मित मिग - 21 वायुयान श्रृंखला का परिचालन कर रही थी। इनमें से अधिकतर वायुयान अपना कुछ तकनीकी जीवन पूरा करने वाले थे तथा 1990 के दशक में फेज आऊट किए जाने थे जिसके परिणामस्वरूप वायु सेना ने युद्ध स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट आई। इसलिए भारतीय वायु सेना ने मिग - 21 बेड़े के वायुयानों को बदलने का प्रस्ताव किया (1980 के दशक के प्रारम्भ में) यह इस पृष्ठपट के विपरीत था कि हल्के लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) का स्वदेशी डिज़ाइन और विकास संस्वीकृति हो गया था (1983) तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वैमानिक विकास एजेंसी, बंगलूर की स्थापना की गई (1984)।

जैसा कि ए एस आर (1985) में विनिर्दिष्ट हैं, एल सी ए, का भारतीय वायु सेना में 1994 तक अधिष्ठापन अपेक्षित था। तथापि एल सी ए कार्यक्रम 1983 की संस्वीकृति से ही पहली बना हुआ था, तथा तीन दशकों के विलम्ब के बावजूद, एल सी ए का भारतीय वायु सेना स्ववाङ्मनों में अभी भी पुनः अधिष्ठापित किया जाना है।

चरणबद्ध विकास के दौरान, एफ एस ई डी चरण II से एफ एस ई डी चरण I में दो प्रोटोटाइपों के अग्रिम निर्माण के ए डी ए के निर्णय से इन दोनों प्रोटोटाइपों के नाजुक ऑन बोर्ड प्रणालियों की कमी पड़ गयी, जिनका शेष तीनों प्रोटोटाइपों पर प्रपाती प्रभाव पड़ा, तथा इन वायुयान के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्राप्त करते समय भारत सरकार को दिए गए वचन के विपरीत ए डी ए उड़ान जांच। मूल्यांकन के प्रति भारतीय वायु सेना के प्रयोग वाले सीमित श्रृंखला उत्पादन वायुयान भी प्रयोग करना पड़ा।

आगे, एल सी ए मार्क - I के लिए आई ओ 53 रियायतें/स्थायी बाज़दावे के साथ प्राप्त हुआ। (दिसम्बर 2013) जो वायुयान की परिचालनात्मक क्षमता तथा उत्तर जीविता सीमित करती है। परिणामतः वर्तमान में विकासाधीन एल सी ए मार्क - I (आई ओ सी/एफ ओ सी वायुयान दोनों) में इंजन प्रस्ट प्राप्त करने में तथा प्राचलों जैसे, वायुयान का भार ईंधन क्षमता, 7.62 एम.एम. बुलेट्स के विरुद्ध पायलट का आगे से बचाव आदि को पूरा करने में कमियां थी। स्व-बचाव जैभर जो मूलतः एल सी ए मार्क - I पर फिट किया जाना था, उसे अब एल सी ए मार्क - II पर फिट किए जाने की योजना है, इस प्रकार 40 एल सी ए मार्क - I अब आर डब्ल्यू आर तरंग-1बी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्व-बचाव जैभर के बिना अतः उसकी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता सीमित होगी। इस प्रकार, भारतीय वायुसेना सीमित

**‘हल्के लड़ाकू वायुयान के डिज़ाइन, विकास, विनिर्माण और अधिष्ठापन’
पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

परिचालनात्मक क्षमताओं के साथ 40 एल सी ए मार्क - I को प्रयोग करने के लिए बाध्य होगी, तथा वर्तमान में ए डी ए द्वारा विकसित किए जा रहे हैं एल सी ए मार्क - II के ए एस आर को पूरा करने की उम्मीद है।

भारतीय वायु सेना द्वारा शस्त्रों की पहचान/प्रतिस्थापन/परिवर्तन में विलम्ब तथा एल सी ए को समकालीन बनाने के लिए भारतीय वायु सेना की आवश्यकता के अनुसार उनके एकीकरण के कारण और भी विलम्ब हुआ है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा परियोजना की अप्रभावी मॉनीटरिंग को दर्शाता था।

किसी भी परियोजना को प्रभावी तथा दक्षतापूर्वक पूरा करने के लिए शुरू से ही प्रयोक्ता भागीदारी अनिवार्य होगी। तथापि, एल सी ए कार्यक्रम में सक्रिय प्रयोक्ता (वायु सेना मुख्यालय) भागीदारी नवम्बर 2006 के बाद ही शुरू हुई, यद्यपि आपसी अवधारणन के बेहतर मूल्यांकन के लिए डिज़ाइन दल तथा प्रयोक्ता के बीच निकट विचार विमर्श सुनिश्चित करने के लिए वायु सेना मुख्यालय तथा ए डी ए के बीच सम्पर्क ग्रुप की आवश्यकता हेतु एल सी ए पी डी पी समीक्षा समीति द्वारा काफी पहले 1989 में सिफारिश की गई थी।

यद्यपि ए डी ए ने 70 प्रतिशत स्वदेशीकरण की प्राप्ति का दावा किया, तथापि, इनमें से आधी उप-प्रणालियां आयातित इलेक्ट्रॉनिक संघटकों तथा पुर्जों आदि के साथ विकसित किए जाते हैं। एल सी ए कार्यक्रम कावेरी इंजन मल्टी मोड राडार, स्व बचाव जैमर, आदि के स्वदेशी विकास में सर्वाधिक आघात पहुँचा। 109 एल आर यू के स्वदेशी विकास हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन फरवरी 2014 से लम्बित था।

आठ एल सी ए प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता की स्थापना में एच ए एल द्वारा विलम्ब हुआ जिसने उत्पादन क्षमता संवर्धन में विलम्ब के साथ एल सी ए स्कवाड्रनों का निर्माण प्रभावित किया था। आगे, एल सी ए विकास में विलम्ब के कारण श्रृंखला उत्पादन के निर्माण तथा आपूर्ति में विलम्ब हुआ है।


एल सी ए के विकास और अधिष्ठापन में विलम्ब के परिणामस्वरूप, भारतीय वायु सेना को 20,037 करोड़ की लागत पर मिग बिस, मिग-29, मिराज-2000 तथा विश्वसनीययुद्धक संभावना सुनिश्चित करने के लिए मिग-21 की फेज़िंग आऊट संशोधित करनी पड़ी।

यह मानते हुए कि अन्य वायुयानों को प्रोन्नत करने के लिए भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए उपाय अस्थायी स्वरूप के थे और स्कवाड्रन शक्ति की कमियों को स्थायी रूप से दूर करने के लिए व भारतीय वायुसेना की परिचालनात्मक तैयारी को बनाए रखने के लिए एल सी ए का

'हल्के लड़ाकू वायुयान के डिज़ाइन, विकास, विनिर्माण और अधिष्ठापन'
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

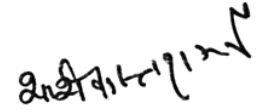
अधिष्ठापन आवश्यक था, सुरक्षा बलों की आवश्यकता पूर्ति हेतु एल सी ए कार्यक्रम को तीव्रगति से पूरा करने की जरूरत है ताकि इस श्रेणी के लड़ाकू वायुयान के आयात से बचाया जा सके तथा दीर्घावधि में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित की जा सके।

नई दिल्ली
दिनांक 21 अप्रैल 2015


(राजीव कुमार पाण्डेय)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वायु सेना

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 21 अप्रैल 2015


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक